भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3883
उत्तर देने की तारीख 18 दिसम्बर, 2024

दूरसंचार नेटवर्क को सुदृढ़ करना

3883. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में दूरसंचार नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशेष योजनाएं तैयार की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की देश भर में विशेषकर देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा 5जी सेवाओं के विस्तार के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार की भारत में टेलीविजन प्रसारण सेवाओं की गुणवत्ता और कवरेज में वृद्धि करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) देश भर में विशेष रूप से देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क को सुदृढ़ करने और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए, सरकार देश के ग्रामीण, दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना करके दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। 4जी सेचुरेशन परियोजना का उद्देश्य देश के सेवा से वंचित 24,680 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान करना है। इस परियोजना

में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा सेवाएं देना बंद करने आदि के कारण 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में सभी 2.64 लाख ग्राम पंचायतों को तथा मांग के आधार पर लगभग 3.8 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट के दायरे का विस्तार करने के लिए 1,39,579 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के साथ संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी है।

(ग) सरकार ने देश में 5जी सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न पहलें की हैं जैसे मोबाइल सेवाओं के लिए नीलामी के माध्यम से पर्याप्त स्पेक्ट्रम का आवंटन, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ई-बैंड में प्रत्येक में 250 मेगाहर्ट्ज के 2 कॅरियरों का अनंतिम रूप से आवंटन, वित्तीय सुधारों की शृंखला जिसके परिणामस्वरूप समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) और बैंक गारंटियों (बीजी) का युक्तिकरण हुआ, एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) की मंजूरी के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण, केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) अनुमोदनों के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल की शुरुआत। इसके परिणामस्वरूप देश के 783 ज़िलों में से 779 ज़िलों में 5जी सेवाएँ उपलब्ध हुई हैं और 31 अक्टूबर, 2024 तक देश में 4.6 लाख से अधिक 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए जा चुके हैं।

(घ) सरकार ने 2021-26 की अवधि के लिए 2539.61 करोड़ रुपये की कुल लागत से एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) को मंजूरी दी है जिसके तहत देश भर में दूरदर्शन नेटवर्क के आधुनिकीकरण और उन्नयन का कार्य शुरू किया गया है। वर्तमान में, दूरदर्शन (डीडी) फ्री डिश, जो एक फ्री-टू-एयर डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा है, की देश भर में पूर्ण कवरेज है और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 10 चैनल की एक विशेष सी-बैंड सैटेलाइट डीटीएच सेवा प्रचालन में है। इसके अतिरिक्त, कुछ वितरण प्लेटफॉर्म नामत: डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) और हेडेंड इन द स्काई (एचआईटीएस) टीवी चैनलों के वितरण के लिए उपग्रहों और एयरवेव्स को नियोजित करते हैं और इस प्रकार अखिल भारतीय कवरेज सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ और पहाड़ी स्थानों में सहजता से सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

*****